

चीनी अनदेखी कर ताइवान से आर्थिक रिश्ते

चीन के साथ संबंध सुधारने की कमी पहले रही आस राष्ट्रपति शी जिनपिंग के राष्ट्रपति बनने से बाद से बिखरने लगी थी और यह स्थिति 2014 में मोदी द्वारा जिनपिंग को दिए गर्मजोशी पूर्ण स्वागत के बावजूद बनी। हकीकत यह है कि चीन लगातार भारत के प्रति आक्रमकता दिखाता आया है, इसका ताजा उदाहरण लद्धाख में भारतीय भूभाग पर कब्जे के प्रयास वाली अभूतपूर्व करतूत है, हालांकि उसको भारत की जोरदार टक्कर का सामना करना पड़ा।

जी. पार्थसारथी

लेखक पूर्ण वरिष्ठ
राजनीतिक है।



हा

ल ही में चीन के साथ पूरबी सीमा पर तनाव पुनः भड़क उठा, जब अरुणाचल प्रदेश में मैक्सोहन सीमारेखा के ठीक

दक्षिण में स्थित सामारिक महत्व के मौनेस्टी शहर के पास चीनी सैनिकों ने अपनी गतिविधियां दिखाईं। वर्ष 1962 के युद्ध में त्वांग पर चीनी सेना ने कब्जा कर लिया था, परंतु युद्ध-विराम उपरांत वापस लौट गई। पहले त्वांग को लेकर चीन के रुख को एक तरह से सीमारेखा की अनाधिकारिक स्वीकारोक्ति माना जाता था और यह भारत-चीन सीमा की निशानदेही करती रही। लेकिन आगे का घटनाक्रम, जैसे कि 1986 में त्वांग जिले से लगाती सुमदोरेंग-चू घाटी में चीनी घुसपैठ ने साफ संकेत कर दिया कि चीन यथास्थिति को चुनौती देने को तैयार है। लद्धाख में मौजूदा तनाव त्वांग के साथ लगते क्षेत्र में है।

चीन के साथ संबंध सुधारने की कमी पहले रही आस राष्ट्रपति शी जिनपिंग के राष्ट्रपति बनने से बाद से बिखरने लगी थी और यह स्थिति 2014 में नवनिवार्चित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जिनपिंग को दिए गर्मजोशी पूर्ण स्वागत के बावजूद बनी। हकीकत यह है कि चीन लगातार भारत के प्रति आक्रमकता दिखाता आया है, इसका नवीनतम उदाहरण लद्धाख में भारतीय भूभाग पर कब्जे के प्रयास वाली अभूतपूर्व करतूत है, हालांकि उसको भारत की जोरदार टक्कर का सामना करना पड़ा।

बेशक वहां फिलहाल बल प्रयोग विराम लागू है किंतु चीन भारतीय इलाके पर जमा ऊहा है। इसके अलावा अब भारत को अरुणाचल प्रदेश में चीनी घुसपैठ का सामना करना पड़ रहा है। लद्धाख और अरुणाचल प्रदेश की घटनाओं से भारतभर में शी जिनपिंग की नीतयत को लेकर अविश्वास है।

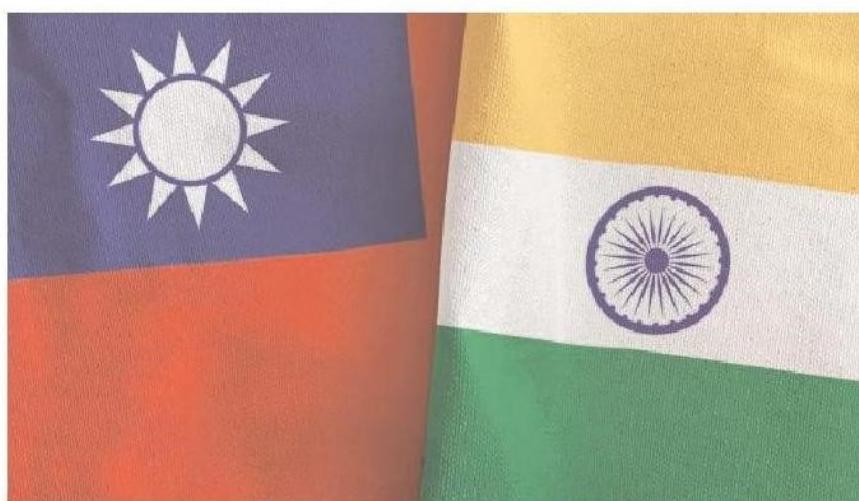
गौरतलब है कि शी जिनपिंग द्वारा राष्ट्रपति का पदभार संभालने से पहले वाले सालों में, 1 अप्रैल, 2005 को 'सीमा विवाद हल एकमुश्त समझौता' यानी 'पैकेज सेटलमेंट' के दिशा-निर्देश सिद्धांतों पर सहमति बन

गई थी। इसमें कहा गया था 'परस्पर सम्मान और समझ की भावना के तहत दोनों पक्ष सीमारेखा पर अपनी-अपनी मौजूदा स्थितियों में लेन-देन करने को राजी हैं ताकि इलाकाई विवाद सदा के लिए खत्म हो सके। इसके लिए सीमारेखा की निशानदेही सुसँगठ और आसानी से पहचाने जा सकने वाले प्राकृतिक और भौगोलिक चिह्नों द्वारा की जाएगी, जो दोनों पक्षों को मंजूर हो।' आगे कहा 'सीमा संधि के मुताबिक दोनों पक्षों को अपनी-अपनी वास्तविक स्थिति में यथेष्ट बदलाव करने होंगे। शी

के बीच मतभेद होना नई बात नहीं परंतु पद से उत्तर चुके वरिष्ठ सदस्यों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार की रिवायत रही है। जिस वक्त सुरक्षा कर्मी हूँ जिन्ताओं को बैठक से बलपूर्वक हटा रहे थे, शी जिनपिंग अपने पूर्ववर्ती की यह बेड़जती चुपचाप देखते रहे। इस बीच, सुधारवाद के पक्षधर प्रधानमंत्री ली किंयांग को कार्यकाल पूरा होने के बाद बदल दिया गया है और उनकी जगह जिनपिंग के चाटुकार ली किंयांग ने ली है।

जापान और दक्षिण कोरिया जैसी इलेक्ट्रॉनिक्स शक्ति बनने की सख्त जरूरत है। इसके लिए जरूरी है कि इनकी तरह भारत में भी इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग का विकासनीय आधारभूत ढांचा हो ताकि सेमीकंडक्टर और कम्प्यूटर चिप्स जैसे महत्वपूर्ण पुज़ों की डिजाइनिंग, विकास और उत्पादन यहां हो सके। अब मोदी सरकार ने तय किया है कि ताइवान के सहयोग से भारत अपना आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग स्थापित करेगा और इस सहयोग पर चीन की प्रतिक्रिया और रोक-टोक की परवाह नहीं करनी है।

ताइवान के साथ बड़े स्तर पर औद्योगिक सहयोग बनाने पर चीन का कोणपाज़न बनने के विषय भय को तज़कर भारत ने अब औपचारिक रूप से बोषणा कर दी है कि बेदांता उद्योग समूह जल्द ही गुजरात में महत्वपूर्ण सेमीकंडक्टर उत्पादन इकाई का नींव पत्थर रखने जा रहा है। ताइवान की विशालकाय टेलीकॉम कंपनी फॉक्सकॉन की भागीदारी वाली इस परियोजना में 20 बिलियन डॉलर का आरंभिक निवेश होना है और संकेतों के अनुसार शीघ्र इसमें निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा और उत्पादन 2024 तक। इससे भारत भर में इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग का विस्तार होने की राह खुलेगी। फिलहाल महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में विशेष इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग कलस्टर बनाए जाने की बात है। जाहिर है कि इलेक्ट्रॉनिक्स क्षमता भारत के विशाल आईटी उद्योग के लिए और फायदेमंद होगी। यह भारत सरकार को देखना है कि इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग का विस्तार देशभर में हो सके। यहां गौरतलब है कि भू-राजनीतिक रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के विकास में चीन दुनिया का पसंदीदा गंतव्य स्थल और विशेष भागीदार पहले जितना नहीं रहा। एप्पल कंपनी अपना आई-फोन उत्पादन चीन से भारत में लाने की प्रक्रिया में है और आईपैड एवं होमपैड का उत्पादन विद्युतनाम ले जा रही है। कदाचित अमेरिकी व्यापार के लिए भी चीन को अधिमान अब नहीं रहा, जबकि वर्ष 1978 से यहां हो रहा था जब तत्कालीन चीनी नेता देंग शियाओं पिंग ने वाशिंगटन यात्रा के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन को शीशे में उतार लिया था। भारत में हाई-टेक उद्योग स्थापना में निवेश पर अमेरिकी नीतियां क्या होंगी, अब बहुत कुछ इस पर निर्भार करता है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग मौजूदा कोविड लहर से बनी अपने लोगों की मुसीबतों को कैसे दूर करते हैं, यह देखना बाकी है।



जिनपिंग के राज वाले चीन के साथ यह संधि सिरे चढ़ पाएंगी, इस पर बहुत शक है, क्योंकि चीन के अपने लगभग तमाम पड़ोसी मूल्कों के साथ थलीय या जलीय सीमा विवाद जारी हैं और दुनियाभर में ऐसा और कोई देश नहीं है।

शी जिनपिंग के नेतृत्व वाले वर्तमान चीन से बरतते वक्त यह बात जहन में रखनी होगी कि अपने विरोधियों से व्यवहार में वे प्रतिरोधी और विवैला रुख रखते हैं, चाहे वह अंदरूनी हो या बाहरी। चीन की स्वयंपोषित सागरीय सीमारेखा रखा नीति में नियंत्रण पाने को बल प्रयोग करना एक अवयव है। हालांकि दुनिया को ज्यादा झटका जिनपिंग के उस तरीके से लगा जब 22 अक्टूबर को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के अधिवेशन के दौरान उन्होंने अपने पूर्ववर्ती हूँ जिन्ताओं का सार्वजनिक तिरस्कार करवाया। सत्तारूढ़ प्रशासन के अधिकांश वरिष्ठ सदस्यों

भारत के विषय में, लगता है शी जिनपिंग अपनी मौजूदा नीति आगे भी जारी रखेंगे और लद्धाख और अरुणाचल प्रदेश में टुकड़ों-टुकड़ों में इलाका कब्जाने वाली चीनी रणनीति भी शायद जरी रहे। हालांकि भारत ने पिछले दो दशकों में चीनी सीमा पर अपने सङ्क तंत्र में विस्तार के लिए बड़े स्तर पर यत किए हैं, फिर भी सीमांत क्षेत्र में सङ्क और संपर्क मामले पर बहुत कुछ करना बाकी है। ज्यादा अहम यह है कि क्या अगले साल भारत की मेजबानी में जी-20 के शिखर सम्मेलन में शी जिनपिंग भाग लेने आएंगी या नहीं।

जैसा कि सबको पता है, भारत लंबे अरसे से ताइवान के साथ प्रगाढ़ व्यापारिक संबंध स्थापित करने को लेकर बिना बात अति-सतरक्ता बरतता आया है। पिछले दो दशकों में साफ दिखा है कि यदि भारत को आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स औद्योगिक उत्पादन की धुरी बनाना है तो